संख्याःपी.एल.जी. पीएफ (एफ) 3-7/2019-20 (एसपीबी /एटीआर)
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2
2. सभी उप-कुलपति, विश्वविद्यालय,
   हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-2 27 फरवरी, 2019

विषयः **माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 16 जनवरी, 2019 को आयोजित हुई बैठक की कार्यवाही ।**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 16 जनवरी, 2019 को हुई बैठक की कार्यवाही सलंग्न करने का निर्देश हुआ है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित मदों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही की रिर्पोट योजना विभाग को भेजने की कृपा करें ताकि उसे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की सूचना एवं जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

2. बैठक की कार्यवाही योजना विभाग की बैबवसाईट https: / /hpplanning.nic.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला -2 27 फरवरी, 2019

राज्य योजना बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित हैः-

1. राज्य योजना बोर्ड के सभी गैर -सरकारी सदस्य।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला -2
3. निजी सचिव माननीय ..... मन्त्री
   हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

4. निजी सचिव मुख्य सचिव,हिमाचल प्रदेश सरकार , शिमला –2
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री , हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त प्रभागाध्यक्ष, योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि वे अपने प्रभाग से सम्बन्धित मदों पर वांछित कार्यवाही करे।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला –2

हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की 16 जनवरी, 2019 को माननीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार (आर्मसडेल भवन) में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

(बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है)

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 16 जनवरी,2019 को प्रातः 11बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभागार में माननीय मुख्यमन्त्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वर्ष 2019–20 के प्रस्तावित वार्षिक योजना आकार को अनुमोदित करवाने हेतू आयोजित की गई।

2. सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) श्री अनिल कुमार खाची ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, प्रदेश मन्त्रीमण्डल के माननीय सदस्यों, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड, माननीय विधायक, राज्य योजना बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों, मुख्य सचिव एवं उपस्थित प्रशासनिक सचिवों/ अधिकारियों का स्वागत करते हुए बोर्ड को अवगत करवाया कि बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2019–20 के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के बहुमूल्य विचारों एवं सुझावों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि वार्षिक योजना (2019–20) के नियोजन में सतत विकास लक्ष्य अभिन्न अंग रहे हैं। तथा इन सतत् विकास लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 30 नई योजनाएं शुरू की है ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को 2022 या इससे पूर्व ही प्राप्त किया जा सके। उन्होनें ने कहा कि इस बैठक में माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए चालू कुछ योजनाओं में आवश्यक बदलाव किए जाने का प्रयास भी किया जाएगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त किया जा सके तथा आम जनता को इनका लाभ एवं सुविधा प्राप्त हो सके।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने सदन को अवगत करवाया कि वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित वार्षिक योजना आकार 7100 करोड़ रूपये का है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष की योजना की तुलना में 800 करोड़ रूपये अधिक है यानि लगभग 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वार्षिक योजना 2019–20 के परिव्ययों में से अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 1788 करोड़ रूपये, जनजातीय उप योजना के लिए 639 करोड़ रूपये तथा पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ताकि प्रदेश के सभी वर्गो का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकें । सरकार ने सामाजिक सेवा शीर्ष को इस वार्षिक योजना में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की है जिसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य शामिल है जिसके लिए 3048.15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। परिवहन एवं संचार क्षेत्र को दूसरी प्राथमिकता देते हुए 1241.98 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। इसी तरह कृषि एवं

सेवा क्षेत्र के लिए 877 करोड़ रूपये एवं उर्जा क्षेत्र के लिए 711 करोड़ रूपये आबंटित किये है।

4. तत्पश्चात माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड श्री रमेश चन्द धवाला ने माननीय मुख्यमन्त्री, राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों, प्रशासनिक सचिवों तथा अन्य अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया तथा सभी उपस्थित सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए।

5. इसके पश्चात माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में बैठक में उपस्थित माननीय मन्त्रियों तथा अन्य उपस्थित सभी माननीय सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत किया। माननीय मुख्यमन्त्री ने बोर्ड को अवगत करवाया कि इस बैठक से पूर्व माननीय विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकता की बैठक आयोजित की जाती है ताकि माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों को वार्षिक योजना में सम्मलित किया जा सके। राज्य योजना बोर्ड में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेषज्ञों को गैर –सरकारी सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके। उन्होनें सदन को अवगत करवाया कि सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल मे प्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गो के उत्थान व कल्याण के लिए 30 नई योजनाएं प्रारम्भ की है तथा उन्हें मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंनें बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम को अपार सफलता प्राप्त हुई है तथा मनानीय प्रधान मन्त्री महोदय ने प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर धर्मशाला में आयोजित जन– आभार रैली में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की है। प्रदेश में अब तक 9 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है जिनमें 22000 के लगभग जन शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्जवला योजना के लाभ से वंचित वर्ग के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई है जिसमें अब तक लगभग 35000 लाभार्थियों को गैस चूल्हे वितरित किए जा चुकें है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना में वंचित लाभार्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने हिम –केयर योजना का शुभारम्भ किया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने विभिन्न विकास के मुददों को केन्द्र सरकार के समक्ष गम्भीरता से उठाया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 9500 करोड़ रूपये की बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएं सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अन्त में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय नें बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से प्रदेश के सर्वागींण विकास कि लिए सुझावों एवं विचारों को आमंत्रित किया।

6. इसके पश्चात सचिव (योजना) द्वारा वार्षिक योजना 2019–20 के मुख्य बिन्दुओं पर Power Point Presentation दी गई जिसमें प्रदेश के विकास की वर्तमान स्थिति से सदन को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या स्थिति है का भी ब्यौरा दिया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि वार्षिक योजना की नियोजन प्रक्रिया में सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) अभिन्न अंग रहे हैं तथा इन लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए नई योजनाएँ आरम्भ करने तथा चालू योजनाओं को इन लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए बदलाव किए जाने का प्रयास भी किया गया है। उन्होंने वार्षिक योजना 2019–20 के मुख्य घटकों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, नाबार्ड तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों का भी ब्यौरा दिया। सचिव (योजना) द्वारा राज्य सरकार के समक्ष पेश आ रही वित्तीय एवं विकासात्मक चुनौतियों से भी सदन को अवगत करवाया गया।

7. श्री अनिल किमटा माननीय गैर–सरकारी सदस्य ने राज्य योजना बोर्ड की बैठक को 2 माह में एक बार उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित करवाने का सुझाव दिया। उन्होनें यह भी कहा कि राज्य योजना बोर्ड के सदस्य, लोगों से सुझाव लेकर राज्य योजना बोर्ड के विचारार्थ रखें । पिछड़ा क्षेत्रों में पैदा होने वाली विभिन्न फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए तथा निजी क्षेत्र को भी इसमें आमंत्रित करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों द्वारा सेब के पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों को काटने की बजाए वन समितियों के माध्यम से इनकी पैदावार को बाजार मे बेचकर सरकार एवं समितियों में प्राप्त राजस्व को बांटा जाना चाहिए। कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

8. श्री प्रेम सिंह व्रैक माननीय गैर–सरकारी सदस्य ने अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत सीधे तौर पर इस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों / कार्यक्रमों में व्यय को बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होनें कहा कि अनुसूचित जाति उप–योजना को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के लिए संस्थागत ढांचा/ विभाग (नोडल विभाग) को सक्षम बनाने तथा मानव संसाधन की कमी को दूर करने का सुझाव दिया। उन्होनें पूर्व में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप–योजना को कार्यान्वित करने हेतु बनाए गए दिशा–निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने का भी सुझाव दिया। उन्होनें प्रदेश में अनुसूचित जाति उप–योजना को कार्यान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की तर्ज पर विधेयक लाने तथा इस पर कानून बनाये जाने का भी सुझाव दिया।

9. श्री एच.सी. शर्मा, उप–कुलपति (बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी) ने कृषि एवं उद्यान में अनुसंधान, विकास एवं विस्तार पर निवेश को बढ़ावा देने का सुझाव दिया तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान का 20 प्रतिशत भाग कृषि एवं उद्यान के अन्तर्गत अनुसंधान, विकास एवं विस्तार के लिए कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों को दिए जाने की बात कही।

10. श्री अशोक कुमार सरियाल, उप–कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड की तर्ज पर सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं जैसे पौंड , बाँध इत्यादि के निर्माण कार्यो में MGNERGA श्रमिकों को सम्मिलित किया जाए। राज्य के सम्पन्न लोगों द्वारा कृषि करना छोड़ दिया है अतः इन खाली पड़े खेतों में भी MGNERGA के श्रमिकों को उपयोग में लाया जा सकता है।

11. श्री एस0पी0 बसंल, उप–कुलपति, तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर ने प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के कम हो रहे Enrollment ratio पर चिन्ता व्यक्त करते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवता पर विशेष ध्यान दिया जाने का सुझाव दिया। राज्य योजना बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित करने का तथा तकनीकी विश्वविद्यालय को मिलने वाले अनुदान को भी बढ़ाए जाने का आग्रह किया। उन्होनें प्रदेश के तीन सैक्टरों उच्चतर शिक्षा, उद्योग तथा तकनीकी शिक्षा पर Planning Frame Work Action Plan बनाने की बात कही जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सैक्टर में 20 प्रमुख लक्ष्यों का निर्धारण कर इनकी प्राप्ति निर्धारित समय पर पूरा करने का सुझाव दिया तथा इसी तरह बाकी सैक्टरों में भी काम करने की बात कही।

12. श्री संजय शर्मा, माननीय गैर–सरकारी सदस्य ने इस बैठक का एजेन्डा बैठक से 2–3 दिन पहले दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होनें पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने तथा हैलीटैक्सी सेवा में प्राईवेट निवेशकों को अनुदान का प्रावधान करने हेतु नीति तैयार करने की बात कही। उन्होनें कहा कि पर्यटकों को बेवजह जगह–जगह न रोका जाए बल्कि एक ही entry point पर ही चैक किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होनें Tourist Friendly Police के गठन की भी बात कही।

13. श्री मनोज चड्डा, माननीय गैर–सरकारी सदस्य ने Organic Farming तथा Exotic Vegetables पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होनें पिछड़ा क्षेत्रों में पैदा होने वाली फसलों को मार्किट तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने तथा पिछड़ा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे इत्यादि को PPP मोड पर बढ़ावा देने के लिए आकर्षक नीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होनें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्कता तथा प्रदेश की विभिन्न Municipalities को ग्रीन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की भी बात कही।

14. श्री नरेन्द्र ठाकुर, माननीय विधायक हमीरपुर, ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न कम्पनियां पीने के पानी व जूस इत्यादि की सप्लाई प्लास्टिक की बोतलों में करते हैं । इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए इन कम्पनियों को यह आदेश दिया जाए कि वे इन खाली बोतलों को recollect and recycle करके उपयोग में लाएं तथा Polluter pay

principal को भी अमल में लाया जाए । उन्होनें शून्य बजट खेती को उच्च स्तर पर भी चलाए जाने का सुझाव दिया।

15. श्री रविन्द्र कुमार, महा–प्रबन्धक, नाबार्ड ने कहा कि नाबार्ड द्वारा भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में बनाई गई विभिन्न 75 Farmer Producer Organizations को उच्च स्तर पर लाया जाए तथा ऐसी organizations के लिए प्रदेश सरकार कोई नीति बनाए व इन्हें कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करे। लघु एवं सीमान्त किसान जिन्होनें कारपोरेशन बैंक से ऋण लिया है उन्हें त्रण में कुछ subvention दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होनें Digitalization को कृषि क्षेत्र में भी उपयोग पर बल दिया ताकि मिटटी की गुणवता, पानी, खाद से लेकर मार्किट तक के उपायों को किसानों तक digitalization के माध्यम से समय पर उपलब्ध करवाया जा सकें। उन्होने इस तरह के उपायों को पॉयलट स्तर पर किसी एक विकास खण्ड या जिले में शुरू किए जाने का भी सुझाव दिया।

16. बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर माननीय गैर–सरकारी सदस्य ने Resource Management के लिए एक उचित व्यवस्था स्थापित करने की बात कही। उन्होने पर्यटन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य, साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन पर ध्यान देने की बात कही।

17. श्री बलवीर वर्मा, माननीय विधायक, चौपाल ने अनुसूचित जाति उप–योजना में किए जाने वाले विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत स्कीमों / कार्यक्रमों में अतिरिक्त बजट प्रावधान करने का सुझाव दिया ताकि इन कार्यो को समयबद्ध पूरा किया जा सके। उन्होने कार्यो को Prioritize करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अनुसूचित जाति बस्तियों में एक मॉडल ढांचा बनाया जा सके। उन्होने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य केन्द्र (Soil testing lab) स्थापित किए जाने का भी सुझाव दिया।

18. श्री सुख राम चौधरी, माननीय विधायक, पांवटा साहिब ने अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को प्राकक्लन के अनुसार पर्याप्त बजट प्रावधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होने प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में वन समितियाँ बनाने का सुझाव दिया तथा खाली वन क्षेत्रों को वन समितियों को आंबटित करके वहां मिटटी की गुणवता अनुसार पेड़ लगाए जा सके। इन वन समितियों को यह भी अधिकार दिया जाए कि वे इन फलदायक पेड़ों से प्राप्त राजस्व को 50 प्रतिशत वन समितियों में तथा 50 प्रतिशत वन विभाग में आंबटित कर सकें जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होने सिंचाई क्षेत्र में व्यवहारिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता तथा किसानों को 50 प्रतिशत उपदान देकर सिंचाई की योजनाओं में भागीदारी बनाने पर बल दिया ताकि यह योजनाएं समय पर पूर्ण हो सकें। किसानों को मुफत बिजली अथवा कुछ उपदान, ट्रैक्टरों के लिए दिए जाने वाले उपदान में अधिक राशि का प्रावधान तथा कृषि उपकरणों पर उचित उपदान दिये जाने का सुझाव दिया।

19. श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक, बिलासपुर ने प्रदेश में कृषि, पर्यटन तथा ढांचागत निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होने कृषि एवं उद्यान से प्राप्त पैदावार को cold storage एवं मार्किट तक पहुंचाने हेतु उचित व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उन्होने सड़कों के रख–रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाने का सुझाव दिया ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

20. श्री राज कुमार वर्मा, माननीय गैर सरकारी सदस्य (सांई इंजिनियरिंग फॉउन्डेशन), ने संसाधन प्रबन्धन की आवश्यकता तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं समीक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होने विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों /योजनाओं को समेकित किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि सरकारी व्यय को सुनियोजित किया जा सके। उन्होने Self Employment को बढ़ावा देने हेतु Self Employment programmes में दिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया।

21. श्री जिया लाल, माननीय विधायक, भरमौर ने Power Corporation को जन–जाति उप–योजना से किए जाने वाले बजट प्रावधान को बन्द करने की बात कही । उन्होनें उड़ान–2 में जनजातिय क्षेत्रों को भी शामिल करने, जनजातिय क्षेत्रों में आंबटित जल–विद्युत परियोजनाओं को जल्दी से शुरू करने एवं काम न करने वाली कम्पनियों के टैंडर को रद्द करने की भी बात कही।

22. कुमारी प्रज्वल बस्टा, BDC Chairman ने गांवों व दूर–दराज के क्षेत्रों में प्रदेश की संस्कृति से सम्बन्धित पर्यटन को बढ़ाना देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होने इन क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नीति बनाने की भी बात कही।

23. श्री ज्योति कपूर, माननीय गैर –सरकारी सदस्य ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है तथा इन केन्द्रों का सही उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। उन्होने साहासिक पर्यटन के लिए दिए जाने वाले लाईसैंस प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता तथा नए पयर्टन क्षेत्रों की तलाश करके Rafting and Adventure Tourism के विस्तार पर भी जोर दिया।

24. विनोद कुमार, माननीय विधायक, नाचन, ने अनुसूचित जाति उप–योजना से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में बजट प्रावधान की 10 प्रतिशत की शर्त को हटाए जाने का सुझाव दिया क्योंकि 10 प्रतिशत की इस शर्त से बहुत सारी स्कीमों का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होने यह भी बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में खयुरी से सुन्दरनगर तक पड़ने वाले क्षेत्र में BBMB के पास बहुत सारी सरकारी उपजाऊ भूमि खाली पड़ी है जिसे वापिस लेने की व्यवस्था पर गहन चिन्तन करने की आवश्यकता है।

उन्होने खयूरी के पास 42 मैगावाट का विद्युत परियोजना लगाने की दिशा में काम करने की बात भी कही।

25. श्री सुरेन्द्र शौरी विधायक, बंजार ने पिछड़ी घोषित पंचायतें जो आज के समय में अग्रणी हो गई हैं को मिलने वाले वित्तीय लाभ को अन्य दूर –दराज की विकास से वंचित पंचायतों को प्रदान करने का सुझाव दिया।

माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिए गए निर्देशः–

1. माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं मे प्रत्येक विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित स्कीमों को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ।
2. प्रत्येक विधायक अपनी अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित प्राथमिकताओं में अलग से उन स्कीमों को भी शामिल करें जिनका कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका हो।

*****

LIST OF PARTICIPANTS

Annexure-'क'

Sr. No.	Name	Designation
1.	Shri. Mahender Singh Thakur	Hon'ble Irrigation & Public Health, Horticulture, Sainik Welfare Minister.
2.	Shri. Suresh Bhardwaj	Hon'ble Education, Parliamentary Affairs, Law and Legal Remembrancer Minister.
3.	Shri. Anil Sharma	Hon'ble Multi Purpose Projects and Power Minister., Non Conventional Energy Sources Minister.
4.	Shri. Ram Lal Markanda	Hon'ble Agriculture, Tribal Development, Information and Technology Minister.
5.	Shri. Govind Singh	Hon'ble Forest, Transport, Youth Services and Sports Minister.
6.	Shri. Ramesh Chand Dhawala	Deputy Chairman, State Planning Board, Himachal Pradesh.
7.	Dr. Shrikant Baldi	Addl. Chief Secy. cum Principal Secy. to Chief Minister, Addl. Chief Secy. (Information & Public Relations), Chairman HPSEB.
8.	Smt. Manisha Nanda	Addl. Chief Secy. (Public Works), Financial Commissioner (Revenue).
9.	Shri. Anil Kumar Khachi	Addl. Chief Secy. (Finance, Planning, Economics & Statistics, Twenty Point Programme).
10.	Shri. Ram Subhag Singh	Addl. Chief Secy. (Tourism & Civil Aviation, Forests).
11.	Smt. Nisha Singh	Addl. Chief Secy. (Printing & Stationery, Labour & Employment, Social Justice & Empowerment).
12.	Shri. Sanjay Gupta	Addl. Chief Secy. (Ayurveda, Animal Husbandry, RPG).
13.	Shri. Manoj Kumar	Addl. Chief Secy. (Home, Industries, Technical Education).
14.	Shri. R.D. Dhiman	Addl. Chief Secy. (Health & Family Welfare, Personnel, Training, FA, Horticulture, Env. Sci. & Tech.) & Chairman HPSPCB.
15.	Shri. Prabodh Sexena	Principal Secy. (MPP & Power, NCES, Urban Dev., Town & Country Planning, Housing) & Chairman, HP Appellate Sales Tax Tribunal.
16.	Shri. Jagdish Chander Sharma	Principal Secy. (Excise & Taxation, Transport, Information Technology).

17.	Shri. Kamlesh Kumar Pant	Principal Secy. (Education) & Financial Commissioner (Appeals).
18.	Shri. Onkar Chand Sharma	Principal Secy. (Tribal Development, Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Agriculture, Cooperation).
19.	Shri. Sanjay Kundu	Addl. Pr. Secy. to Chief Minister Principal Secy. (Vigilance) Pr. Resident Commissioner HB New Delhi.
20.	Shri. Yashwant Singh	LR-cum-Pr. Secretary (Law).
21.	Shri. Devesh Kumar	Secretary (Irrigation & Public Health).
22.	Dr. Ravinder Nath Batta	Secretary (Rural Development, Panchayati Raj, Project Monitoring to Chief Minister, General Admn., Parl. Affairs, Secretariat Admn., Sainik Welfare).
23.	Dr. Purnima Chauhan	Secretary (Administrative Reforms, Language Art & Culture).
24.	Shri. Akshay Sood	Secretary (Finance).
25.	Smt. Sushma Thakur	Under Secretary, YSS Department.
26.	Dr. Arun Sharma	Director, State Forensics Lab, Junga .
27.	Prof. Ashok Kumar Sarial	VC, CSKHPKV Palampur University.
28.	Dr. H.C. Sharma	VC, UHF, Nauni University, Solan
29.	Prof. Sikander Kumar	VC, Himachal Pradesh University, Shimla.
30.	Prof. S.P. Bansal	VC, Himachal Pradesh Technical University.
31.	Shri. Ravinder Kumar	General Manager, NABARD.
32.	Dr. B.R. Premi	Dy. General Manager, NABARD.
33.	Dr. Vinod Rana	Adviser, Economics & Statistics Department.
34.	Shri. Rajesh Sharma	Director, Women & Child Development Department.
35.	Shri. C.K Chaturvedi	Chief Engineer, HPSEBL.
36.	Shri. Harbans Singh Brascon	Director, Information & Public Relation Department.
37.	Shri. M.L. Dhiman	Director, Horticulture Department.
38.	Shri. Rajinder Dutt Sharma	Joint Controller, Excise & Taxation Department.
39.	Shri. Bhagat Singh Thakur	SP Welfare, Police Department.
40.	Shri. R.P Verma	Engineer-in-Chief, HPPWD.
41.	Dr. S.S. Guleria	Commissioner, Labour & Employment Department.
42.	Shri. Suman Vikrant	Engineer-in-Chief (IPH).
43.	Shri. S.R. Mardi	Director General of Police, Himachal Pradesh.
44.	Shri. Kailash Chauhan	Dy. Director, Rural Development Department.

45.	Smt. Suman Rawat Mehta	Addl. Director, Youth Services & Sports Department.
46.	Shri. Madan Kumar Minhas	Superintending Engineer (P&M, HPPWD).
47.	Shri. Sakini Kapoor	CM Security.
48.	Shri. P.S. Draik	IAS (Rtd), Non-Official Member.
49.	Shri. Balbir Verma	MLA, Chopal, Non-Official Member.
50.	Shri. Narender Thakur	MLA, Hamirpur, Non-Official Member.
51.	Shri. Subhash Thakur	MLA, Bilaspur, Non-Official Member.
52.	Shri. Jai Lal	MLA, Bharmor, Non-Official Member.
53.	Shri. Vinod Kumar,	MLA, Nachan, Non-Official Member.
54.	Shri. Rakesh Jamwal	MLA, Sundernagar, Non-Official Member.
55.	Shri. Surinder Sourie	MLA, Banjar, Non-Official Member.
56.	Shri. Ram Chand Bhatiya	Ex. MLA Nagrota, Non-Official Member.
57.	Smt. Vinod Kumari	Ex. MLA Doon, Non-Official Member.
58.	Shri. Govind Sharma	Ex. MLA Arki, Non-Official Member.
59.	Shri. Rikhi Ram Kondal	Ex. MLA Non-Official Member
60.	Shri. Dulo Ram	Non-Official Member, State Planning Board.
61.	Smt. Prajwal Busta	Non-Official Member, State Planning Board.
62.	Shri. Manoj Chadha	Non-Official Member, State Planning Board.
63.	Shri. Anil Kimta	Non-Official Member, State Planning Board.
64.	Shri. Sanjay Sharma	Non-Official Member, State Planning Board.
65.	Shri. Sanjay Guleria	Non-Official Member, State Planning Board.
66.	Smt. Veena Thakur	Non-Official Member, State Planning Board.
67.	Shri. Yuvraj Bodh	Non-Official Member, State Planning Board.
68.	Shri. Raj Kumar Verma	Non-Official Member, State Planning Board.
69.	Dr. K.R. Dhiman	Non-Official Member, State Planning Board.
70.	Shri. Jyoti Kapoor	Non-Official Member, State Planning Board.
71.	Brig. Khushal Thakur	Non-Official Member, State Planning Board.
72.	Shri. Surender Paul	Joint Director, Planning Department.
73.	Smt. Kamla Verma	Deputy Director , Planning Department.
74.	Sh. Ravinder Kumar	Deputy Director , Planning Department.
75.	Sh. R.C. Negi	Deputy Director , Planning Department.
76.	Shri. Tilak Raj Thakur	System Analyst, Planning Department.
77.	Shri. Jaishi Ram	Programme Planning Officer, Planning Department.
78.	Shri. Rajiv Sangrai	Research Officer, Planning Department.
79.	Shri. Pradeep Sharma	Research Officer, Planning Department.
80.	Shri. Naresh Kumar Sharma	Research Officer, Planning Department.
81.	Smt. Sunita Walia	Research Officer, Planning Department.
82.	Shri Vickrant Joshi	Research Officer, Planning Department.
83.	Smt. Suman Negi	Assistant Research Officer, Planning

		Department.
84..	Shri. Hament Sharma	Assistant Research Officer, Planning Department.
85.	Shri. Rakesh Gautam	Statistical Officer, Planning Department.
86.	Ms. Manisha	Steno Computer Operator, Planning Department.